



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, ३ जून, १९९५/१३ ज्येष्ठ, १९१७

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(संसदीय कार्य विभाग)

अधिसूचना

शिमला-२, १९ मई, १९९५

संख्या जी० ए० डी० (पी० ए०) (४) (डी)-९/८८.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, १९७१ (१९७१ का ४) की धारा ७ के साथ संशोधन धारा १३

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 17 अप्रैल, 1981 के राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश अधिसूचना संख्या जी०ए०डी० (पी०ए०) 4 (डी) 46/82 तारीख 2 अप्रैल, 1981 द्वारा प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष (भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण) नियम, 1981 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण) (संशोधन) नियम, 1995 है।

2. नियम 4 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण) नियम, 1981 के नियम 4 के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“4. अधिकतम अग्रिम राशि.—अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यथास्थिति को भवन निर्माण या निर्मित भवन को खरीदने के लिए अग्रिम की अधिकतम राशि चार लाख रुपये या वास्तविक कीमत या भवन निर्माण की लागत जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यथास्थिति ने हिमाचल प्रदेश मंत्री (मोटर कार अग्रिम) नियम, 1971 के नियम 4 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (मोटर कार अग्रिम) नियम, 1971 के नियम 4 या हिमाचल प्रदेश उपमंत्री (मोटर कार अग्रिम) नियम 1971 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (मोटर कार अग्रिम ऋण) नियम 1979, के नियम 4 के अधीन मोटर कार अग्रिम ले रखा हो तो भवन निर्माण अग्रिम की कुल राशि की परिसीमा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यथास्थिति द्वारा पहले से ही लिए गए भवन निर्माण अग्रिम सहित चार लाख रुपये से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और भी तब जहां अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यथास्थिति, ने, मंत्री या उपमंत्री या विधान सभा सदस्य, जैसी भी स्थिति हो कि है नियम में भवन निर्माण अग्रिम ले रखा हो तो भवन निर्माण अग्रिम की कुल राशि की परिसीमा उसे पहले दिए गए भवन निर्माण अग्रिम सहित चार लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।”

[Authoritative English text of Government notification No. GAD (PA) 4 (D)-9/88, dated 19-5-1995, as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th May, 1995

No. GAD (PA) 4 (D)-9/88. —In exercise of the powers conferred by section 13 read with section 7-A of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance of Loan for House Building) Rules, 1981 published in the Himachal Pradesh Rajpatra (Extra ordinary) dated the 17th April, 1981 vide Notification No. GAD (PA) 4 (D)-46/82, dated the 2nd April, 1981, namely :—

1. Short title.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance of Loan for House Building) Amendment Rules, 1995.

2. Amendment of rule-4.—For rules 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance of Loan for House Building) Rules, 1981, the following shall be substituted, namely :—

“4. Maximum amount of advance.—The maximum amount which may be advanced to the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, for the construction of a

house or for the purchase of built up house shall not exceed four lacs rupees or the actual price cost of the construction of house, whichever is less :

Provided that in case the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, has taken the Motor Car Advance under rule 4 of the Himachal Pradesh Ministers (Advance for Motor Car) Rules, 1971 or under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance for Motor Car) Rules, 1971 or under rule 4 of the Himachal Pradesh Deputy Ministers (Advance for Motor Car) Rules, 1971 or under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Advance of Loan for purchase of Motor Car) Rules, 1979, then the total amount of house building advance together with the Motor Car Advance already availed of by the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, shall not exceed the limit of four lacs rupees :

Provided also that where a Speaker or Deputy Speaker, as the case may be, has been taken the Motor Car Advance in his capacity as the Minister or the Deputy Minister or the Members of Legislative Assembly, as the case may be, the total amount of Motor Car Advance together with the Motor Car Advance already given to him shall not exceed the limit of four lacs rupees."

अधिसूचना

शिमला-2, 19 मई, 1995

संख्या जी० ए० डी० (पी० ए०) 4 (डी०)-9/88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मंत्रियों के वेतन और भत्ते (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 3) की धारा 7-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख, 31 मार्च, 1981 के राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना संख्या जी० ए० डी० (पी० ए०) 4 (डी०)-49/78-सी०-जिल्द-II, तारीख, 30 मार्च, 1981 द्वारा प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश मन्त्री (भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण) नियम, 1981 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मन्त्री (भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण) संशोधन नियम, 1995 है।

2. नियम-4 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश मन्त्री (भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण) नियम, 1981 के नियम-4 के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4. अधिकतम अग्रिम राशि.—मन्त्री को भवन निर्माण या निर्मित भवन को खरीदने के लिए अग्रिम की अधिकतम राशि चार लाख रुपये या वास्तविक कीमत या भवन निर्माण की लागत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यदि मन्त्री ने हिमाचल प्रदेश मन्त्री (मोटर कार अग्रिम) नियम, 1971 के नियम 4 के अधीन या हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष (मोटर कार अग्रिम) नियम, 1971 के नियम 4 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (मोटर कार अग्रिम ऋण) नियम, 1979 के नियम 4 के अधीन मोटर कार अग्रिम ले रखा हो तो भवन निर्माण अग्रिम की कुल राशि की परिसीमा मन्त्री द्वारा पहले से ही लिए गए भवन निर्माण अग्रिम सहित चार लाख रुपये से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यहाँ और भी तब जहाँ मन्त्री ने अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उपमन्त्री या विधान सभा सदस्य, यथास्थिति की हैसियत से भवन निर्माण अग्रिम ले रखा हो तो भवन निर्माण अग्रिम की कुल राशि की परिसीमा उसे पहले दिए गए भवन निर्माण अग्रिम सहित चार लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।"

[Authoritative English text of the Government Notification No. GAD (PA) 4 (D)-9/88, dated 19-5-95 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 19th May, 1995

No. GAD (PA) 4(B)-9/88.—In exercise of the power conferred by section 7-A of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 3 of 1971), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Ministers (Advance of Loan for House Building) Rules, 1981, published in the Himachal Pradesh Rajpatra (Extra ordinary), dated the 31st March, 1981 vide Notification No. GAD (PA) 4 (D) 49/78-C-Vol.-II, dated 30th March, 1981, namely:—

1. *Short title.*—These rules may be called the Himachal Pradesh Ministers (Advance of Loan for House Building) Amendment Rules, 1995.

2. *Amendment of rule-4.*—For rule 4 of the Himachal Pradesh Ministers (Advance of Loan for House Building) Rules, 1981, the following shall be substituted, namely:—

“4. **Maximum amount of advance.**—The maximum amount which may be advanced to a Minister for the construction of a house or for the purchase of a built up house shall not exceed four lacs rupees or the actual price or cost of the construction of house, whichever is less :

Provided that in case the Minister has taken the Motor Car Advance under rule 4 of the Himachal Pradesh Ministers (Advance for Motor Car) Rules, 1971 or under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance for Motor Car) Rules, 1971 or under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Advance of Loan for purchase of Motor Car) Rules, 1979, then the total amount of house building advance together with the Motor Car advance already availed of by the Minister, shall not exceed the limit of four lacs rupees.

Provided also that where a Minister has taken the house building advance in his capacity as the Speaker or the Deputy Speaker or the Deputy Minister or the Member of Legislative Assembly, as the case may be, the total amount of house building advance together with the house building advance already given to him shall not exceed the limit of four lacs rupees”.

अधिसूचना

शिमला-2, 19 मई, 1995

संख्या जी० ए० डी० (पी० ए०) 4 (डी०)-9/88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 5) की धारा 8-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु, तारीख, 25 मार्च, 1983 के राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना संख्या जी० ए० डी० (पी० ए०) 4 (डी०)-16/82, तारीख, 22 फरवरी, 1983 द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश उप-मन्त्री (भवन निर्माण के लिए अधिम ऋण) नियम, 1982 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उप मन्त्री (भवन निर्माण के लिए अधिम ऋण) संशोधन नियम, 1995 है।

2. नियम-4 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश उ। मन्त्री (भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण) नियम, 1982 के नियम-4 के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

“4 अधिकतम अग्रिम राशि.—उप मन्त्री को भवन निर्माण या निमित्त भवन को खरीदने के लिए अग्रिम की अधिकतम राशि चार लाख रुपये या वास्तविक कीमत या भवन निर्माण की लागत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यदि उप मन्त्री ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (मोटर कार अग्रिम) नियम, 1971 के नियम 4 या हिमाचल प्रदेश उप मन्त्री (मोटर कार अग्रिम) नियम, 1971 के नियम 4 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (मोटर कार अग्रिम ऋण) नियम, 1979 के नियम 4 के अधीन मोटर कार अग्रिम ले रखा है तो भवन निर्माण अग्रिम की कुल राशि की परि सीमा उप मन्त्री द्वारा पहले से ही लिए गए भवन निर्माण अग्रिम गहिन चार लाख रुपये से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां उप मन्त्री ने, उपाध्यक्ष या विधान सभा सदस्य, यथास्थिति, की हैसियत में भवन निर्माण अग्रिम ले रखा है तो भवन निर्माण अग्रिम की कुल राशि की परि सीमा उसे पहले दिए गए भवन निर्माण अग्रिम को मिला कर चार लाख रुपये से अधिक नहीं होगी” ।

[Authoritative, english text of Government Notification No. GAD (PA) 4 (D)-9/88, dated 19-5-95, as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 19th May, 1995

No. GAD (PA) 4 (D)-9/88.—In exercise of the powers conferred by section 8-A of the Salaries and Allowances of Deputy Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 5 of 1971), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Deputy Ministers (Advance of Loan for House Building) Rules, 1982, published in the Himachal Pradesh Rajpatra (Extra-ordinary), dated the 26th March, 1983 vide Notification No. GAD (PA) 4 (D)-46/82, dated the 22nd February, 1983, namely :—

1. *Short title.*—These rules may be called the Himachal Pradesh Deputy Ministers (Advance of Loan for House Building) Amendment Rules, 1995.

2. *Amendment of Rule-4.*—For rule 4 of the Himachal Pradesh Deputy Ministers (Advance of Loan for House Building) Rules, 1982, the following shall be substituted, namely :—

“4 *Maximum amount of advance.*—The maximum amount which may be advanced to a Deputy Minister, for the construction of a house or for the purchase of a built up house shall not exceed four lacs rupees or the actual price or cost of the construction of house, whichever is less :

Provided that in case the Deputy Minister has taken the Motor Car Advance under rule 4 of the, the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance for Motor Car) Rules, 1971 or under rules 4 of the Himachal Pradesh Deputy Ministers (Advance for Motor Car) Rules, 1971 or under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Advance of Loan for purchase of Motor Car) Rules, 1979 then the total amount of house building advance together with the motor car advance already availed of by the Deputy Minister shall not exceed the limit of four lacs rupees :

Provided also that where a Deputy Minister has taken the house building advance in his capacity as the Deputy Speaker or the Member of Legislative Assembly, as the case may be, the total amount of house building advance together with the house building advance already given to him shall not exceed the limit of four lacs rupees".

By order,

Sd/-

Commissioner-cum-Secretary.